INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 8.031 (SJIF 2025)

"भारतीय अर्थव्यवस्था, परिवर्तनकारी विकास दशक (2014-2024) : एक संक्षिप्त समीक्षा, विशेष सर्वसाधारण बोध हेतु"

(Indian Economy, Transformational Growth Decade (2014-2024): A Brief Review, Specially for General Understanding")

केननक्रांता पटेल
शोधार्थी,
वाणिज्य विभाग,
भारती विश्वविद्यालय,
दुर्ग, छत्तीसगढ़।

डॉ. काजोल दत्ता
शोध निर्देशक,
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग,
भारती विश्वविद्यालय,
दुर्ग, छत्तीसगढ़।

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/03.2025-93362471/IRJHIS2503003

सार :

माननीय वित्त मंत्री द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रस्तुत समीक्षा में वर्ष 2020-25 में भारत की जीडीपी 7% के करीब बढ़ेगी, जिसमें वर्ष 2030 तक 7% से अधिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है ।यह वृद्धि दो चरणों में होंगे -वर्ष 1950 से 2014 और वर्ष 2014 से 2024 तक। यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हैं। जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था (अतीत, वर्तमान और भविष्य) का अवलोकन प्रदान करता है और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और प्रगति पर एक नज़र डालता है। इसमें पिछले दस वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी यात्रा और आने वाले वर्षों में आधुनिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण शामिल है।

***मुख्य शब्द** : भारतीय अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक,शासन, नीति और प्रदर्शन, राष्ट्र और सकल घरेलू उत्पाद, विकास और सुधार, क्षेत्र और दशक।*

"किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक - आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए अर्थ (धन) को केंद्र में रखकर बनाए गए व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है।"

वास्तव में **'अर्थव्यवस्था'** शब्द अधूरा ही रहेगा जब तक की इसके आगे किसी देश या किसी क्षेत्र का नाम ना जोड़ा जाए - जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था**, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था। स्थायित्व

- दृष्टि द विज़न

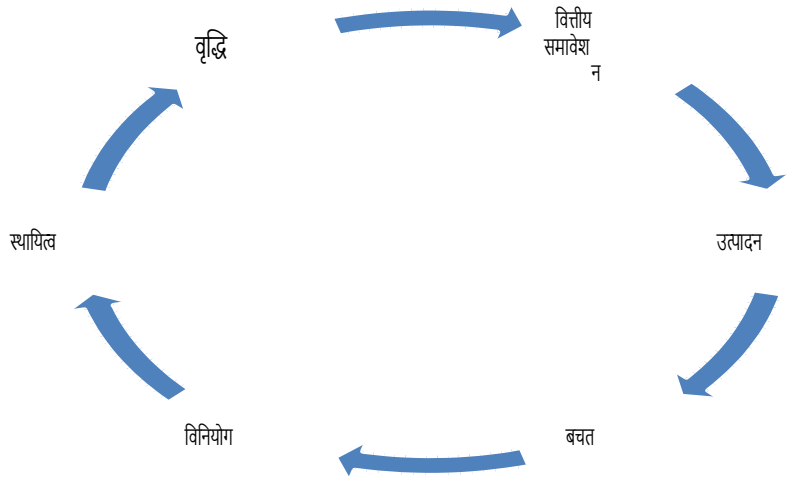

परिचय :-

भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ी होगी। यह एक प्रभावशाली उपलब्धि होगी जो भविष्य के लिए अच्छा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और क्षमता की गवाही देगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड के बाद अपनी रिकवरी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि लगातार झटकों ने इसे झकझोर दिया है। साथ ही विकास एवं सेवाओं, व्यापार और रोजगार, डिजिटल सेवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौती का लाभ उठाएँ।

बजट अनुमानों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश वित्त वर्ष 2015 के 5.06 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 18.06 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ है। इसकी बैलेंस शीट मजबूत है। जन धन योजना के तहत 51 करोड़ बैंक खातों में अब कुल जमा राशि 2.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिनमें से 55% से अधिक महिलाएं हैं। दिसंबर 2019 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद का 52.8% थी और मार्च 2023 तक यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 65.5% हो जाएगी। अर्थव्यवस्था ने कर्मचारियों के लिए रोजगार सृजित किए हैं। कोविड-19 के बाद श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है।कोविड के बाद, विशेषकर महिलाओं के मामले में, सरकार द्वारा अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन जैसी दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान किए जाने से आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ी हैं, जो वास्तव में सरकार की नीतियों और प्रदर्शन का परिणाम है। साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए राष्ट्र और लोगों को स्वयं पर विश्वास करना होगा।

अब, "भारत करता है और भारतीय करते हैं।"

\- (वी. अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार)

<u>विभिन्न शोध साहित्यों की समीक्षा :-</u>

- **बी.बी. भट्टाचार्य और सब्यसाचिकर** "राजकोषीय क्षेत्र में सुधार की कमी और सार्वजनिक निवेश की सुरक्षा में विफलता ने दीर्घावधि विकास की संभावनाओं को कम कर दिया है। वैकल्पिक राजकोषीय नीतियों के अनुभाग में दिए गए परिणामों से यह बात पुष्ट होती है। मौद्रिक नीति के दीर्घकालिक प्रभाव निवेश पर उनके प्रभाव पर निर्भर करेंगे। ब्याज दर या निजी निवेश का समग्र प्रभाव छोटा है। अधिक सार्वजनिक निवेश वाली अधिक साहसिक राजकोषीय नीति को सरकारी व्यय में कमी द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है।"

- **अरविंद विरमानी (2005)** "यह व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वतंत्रता के बाद की पिछली आधी सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था धन पर कम निर्भर हो गई है। 2005 में भारतीय आर्थिक विकास उल्लेखनीय रूप से स्थिर रहा है। विकास के दो चरण 1. समाजवाद का भारतीय संस्करण 2. बाजार सुधारों में प्रयोग। सकल घरेलू उत्पाद पर वर्षा के समग्र प्रभाव पर आपूर्ति पक्ष प्रभाव (जीडीपी में कृषि का आकार) में अपेक्षित गिरावट मांग पक्ष प्रभावों से ऑफसेट हो गई है।"
- **राघवेन्द्र झा,(2007)** दो दशक से अधिक के प्रभावशाली आर्थिक विकास और कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के साथ-साथ विनियमन के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था और भी अधिक वृद्धि की दहलीज पर है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि और आर्थिक सुधारों के बीच संबंध गैर-रेखीय है।
- **नम्रता आनन्द" भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन (1991-2013)** 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक और अशांति के दौर से गुजर रही है। यह विश्वास करना कठिन है कि 2012 में चालू खाता घाटा 1991 के 3% की तुलना में 4% है, 1991 में 8% की तुलना में 2012 में राजकोषीय घाटा 6% है।
- **एम.के. अग्रवाल (2023-24)** ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मानना है कि विकास के पुराने मॉडल कई कारणों से त्रुटिपूर्ण रहे हैं। ये भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं थे। अब कल्याणकारी योजनाओं से लेकर प्रमुख अवसंरचना विकास और प्रौद्योगिकी तथा शासन सुधारों तक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाता है।

अनुसंधान अंतराल :

1). भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी आर्थिक वृद्धि की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए भविष्य में आर्थिक सुधारों से गुजरना होगा। लेकिन, आर्थिक सुधारों पर अल्पकालिक निर्माण हो सकता है, खासकर जब वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से खुद को निभाते हैं।

2) भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि अवधि (2014-2024) का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा जारी रखने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचे का विकास, गरीबी, मनरेगा, रोजगार और तकनीकी परिवर्तन, स्वास्थ्य, पर्यटन, मानव विकास आदि।

शोध कार्य के उद्देश्य -

1. पिछले दशक मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की नीति और प्रदर्शन का विश्लेषण करना।
2. देश के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों पर संरचनात्मक सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन
3. भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास व सुधार के उपाय कार्य योजना भविष्य के लिए ।

शोध पद्धति :

पूरे पेपर का विश्लेषण, अवलोकन विकास दर और माध्यमिक डेटा सरकारी नीतियों और योजनाओं के द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। (2024-2024) की समय अवधि पर आंकड़े संग्रह हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था: अतीत, वर्तमान और भविष्य की विकास गाथा (1950 से 2014)

1950: 1950 के दशक में सरकार ने आर्थिक पर्याप्तता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक रणनीति अपनाई। इस अवधि की विशेषता तेजी से औद्योगीकरण थी, जिसमें भारी मात्रा में संसाधन जुटाना और उन्हें निवेश करना शामिल था। बड़े उद्योगों का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई)।

1952-60: इस अवधि (1952-60) के लिए दशक की औसत वृद्धि दर 3.9% थी। 1960 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी से गुज़रने का गवाह है।

1962, 1965-66: 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965-66 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के साथ-साथ 1965 में भीषण सूखे का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

1970:1970 के दशक में भारतीय रुपये का 57% की तीव्र अवमूल्यन देखा गया, इस दशक की विशेषता राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक स्वतंत्रता में कटौती भी थी, जिसमें 1975 में आपातकाल लागू करना भी शामिल था। बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च के साथ मामूली उदारीकरण के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सुधार हुआ 1980 के दशक में 5.7% तक।

1990-91: बाहरी संकट, अस्थिर सरकारी खर्च और आंतरिक सामाजिक-राजनीतिक माहौल के कारण भुगतान संतुलन संकट पैदा हो गया, जिसने अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए 1991 के भुगतान संतुलन संकट और उसके बाद के सुधारों के लिए एक साहसिक प्रतिक्रिया की मांग की भारतीय आर्थिक प्रक्षेपवक्र क्षण में।

2000: (1998-2000) यह घरेलू आर्थिक गतिविधि में स्थायी गति, बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन, एक अनुकूल निवेश माहौल, एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत के लिए सकारात्मक भावना और वैश्विक तरलता की स्थिति ब्याज दर को प्रोत्साहित करने के कारण वैश्विक विकास में उछाल आया, और भारत में पूंजी प्रवाह में तेजी आयी ।उदाहरण एसएसए, एनआरएचएम, एनआरईजीएस।

(2006-2008):मार्च 2008 को समाप्त वर्ष में ख़राब ऋण अनुपात जल्द ही दोहरे अंक में पहुँच कर 11.2% तक पहुँच गया।

(2009-2014): (2013) अवधि को शुद्ध करते हुए सरकार ने उच्च राजकोषीय घाटा चलाकर और मौद्रिक नीति को लंबे समय तक ढीला रखकर उच्च विकास को बनाए रखने की कोशिश की। उच्च मुद्रास्फीति के कारण नाममात्र जीडीपी वृद्धि अधिक थी। 2013 में यह सब चरम पर पहुंच गया और भारतीय रुपया दुर्घटनाग्रस्त हो गया 2009 और 2014 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में सालाना 5.9% की गिरावट आयी जिससे आर्थिक विकास रूक गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियाँ (वर्ष 2014 से पूर्व) :

1. परियोजना प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने में कठिनाइयों ने व्यापार करने की आसानी को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप विचारणीय परियोजना विलंब और अपर्याप्त पूरक निवेश हुआ।
2. गलत लक्षित सब्सिडी ने सार्वजनिक निवेश के लिए राजकोषीय स्थान को कम कर दिया और संसाधनों के आवंटन को विकृत कर दिया।
3. कम विनिर्माण आधार, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं का, और विनिर्माण में कम मूल्य संवर्धन।

4. एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति और औपचारिक क्षेत्र में अपर्याप्त श्रम अवशोषण। कम कृषि उत्पादकता के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें विपणन के स्तरों में मध्यस्थ की महत्वपूर्ण उपस्थिति, भंडारण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की कमी, कृषि उत्पादों का अंतर-राज्यीय आंदोलन आदि शामिल हैं।

2014 तक विकास के अनुभव से सीख :

भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को 2014 में विरासत में मिली थी। उन विकास की कुछ विशेषताएं हैं:-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई । 1950-1980 की अवधि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात की विशेषता थी। सब्सिडी, और प्रौद्योगिकी और निवेश सहयोग पर कड़े प्रतिबंध। संतोषजनक विनिर्माण उद्योगों के लिए क्षमता विस्तार और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं पर नियंत्रण थे ।इस अवधि के दौरान भी लगाया गया। 1980 के बाद की अवधि में कई व्यवसाय-समर्थक सुधार हुए ।

इस अहसास के बीच कि नियंत्रित शासन अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है। इन नीतिगत परिवर्तनों में आयात उदारीकरण, निर्यात प्रोत्साहन, विनिमय दर नीतियां और शामिल हैं ।विस्तारवादी राजकोषीय नीति. तर्क दिया गया कि इन सुधारों का उत्पादकता बढ़ाने वाला प्रभाव होगा, साथ ही बेहतर ऋण उपलब्धता और उच्च स्तर से मांग बढ़ाने वाला प्रभाव भी संभव हुआ ।सार्वजनिक व्यय इसके साथ ही, उन्हें अस्थिर निवेशों द्वारा सक्षम बनाया गया और संदिग्ध ऋण, प्राकृतिक संसाधनों का अपारदर्शी आवंटन और उच्च राजकोषीय घाटा इसे बढ़ावा दे रहा है । मुद्रास्फीति और बाह्य असंतुलन, जिसके परिणामस्वरूप 1990-91 का बीओपी संकट उत्पन्न हुआ। बीओपी संकट एक बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण व्यापार औद्योगिक नीतियों में सुधार के साथ-साथ नीतिगत सुधारों को वापस लेना भी शामिल है । औद्योगिक लाइसेंसिंग और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण शुरू किया गया।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था जनता के प्रभुत्व से परिवर्तित हो गई । सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व के लिए निवेश। एक महत्वपूर्ण धारणा स्वतंत्रता के बाद की विकास रणनीति के चुनाव में सार्वजनिक क्षेत्र की पीढ़ी शामिल थी ।बचत, जिसका उपयोग उच्च और उच्चतर स्तर के निवेश के लिए किया जा सकता है, हालाँकि, 1970 के दशक में यह अपेक्षा जनक होने के बजाय ग़लत साबित हुई । 1980 के दशक तक, सरकार ने उधार लेना शुरू कर दिया न केवल अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को वित्तपोषित करने के लिए भी निवेश, जैसा कि कुल सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी में तेज वृद्धि में देखा गया था ।

1960-75 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 1980-81 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत हो गया, और 1989-90 तक 9 प्रतिशत तक। भारत का निजी क्षेत्र विकास का प्रमुख इंजन बन गया और 1990 और 2000 के दशक के दौरान रोजगार सृजन हुआ।

3. प्रौद्योगिकी को प्रमुख विकास चालक के रूप में पहचाना जाने लगा। पूर्व-उदारीकरण में भारत मे संसाधनों की कमी, बंद अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी प्रौद्योगिकियों को अस्वीकार कर दिया गया ।शासन, और सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से। जैसा कि प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक ने कहा है।

आर.ए. माशेलकर के अनुसार,

"यह 'तकनीकी राष्ट्रवाद' के मार्ग के माध्यम से था कि भारत ने आत्म-विकास किया।"

नागरिक क्षेत्रों के साथ-साथ रणनीतिक क्षेत्रों जैसे दोनों में अपनी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से निर्भरता अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और सुपर कंप्यूटर"। 1980 के दशक से भारत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। और अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए लगातार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। कुछ सकारात्मक विकासों के बावजूद, यह ध्यान रखना उचित है कि, परकुछ सकारात्मक विकासों के बावजूद, उस समय यह ध्यान देना उचित है ।प्रधान मंत्री मोदी ने 2014 में अपने पहले कार्यकाल में भारतीय राज्य की सत्ता संभाली अर्थव्यवस्था उत्साहवर्धक से कोसों दूर थी। भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही थी । इसका परिणाम दोनों के लिए स्थिर कीमतों पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की 5 प्रतिशत से कम वृद्धि के रूप में निकला ।

4. 2012-13 और 2013-14 वर्ष खाद्य वस्तुओं में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति, जो औसत रही। 2013-14 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में सालाना 12.2 प्रतिशत, गैर-खाद्य से काफी अधिक था । मुद्रा स्फ़ीति, संरचनात्मक बाधाओं का बढ़ना उप-निर्धारण में योगदान देने वाले कारकों में से एक था जिसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- **पिछले दशक में भारत के विकास के संचालक**

सरकार की आर्थिक नीति का फोकस वित्तीय क्षेत्र को पटरी पर लाकर भारत की विकास क्षमता को बहाल करना, व्यापार के लिए परिस्थितियों को आसान बनाकर आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाना और भारत की कनेक्टिविटी बढ़ाने और इसके विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर बढ़ाना था।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण और विलय तथा दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) को बढ़ाने के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन।रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 ने पारदर्शी लेनदेन की संस्कृति बनाई है, काले धन के प्रचलन को कम किया है और इस क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित किया है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1 लाख से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएं और 72,012 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं।देश में कराधान पारिस्थितिकी तंत्र में 2014 के बाद की अवधि में बड़े बदलाव हुए हैं। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनाने जैसे कर नीति सुधार किए गए हैं। जीएसटी प्रणाली ने पूर्व-जीएसटी व्यवस्था की तुलना में बेहतर उछाल दिखाया है, जिसमें औसत मासिक सकल संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 0.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जीएसटी करदाताओं की संख्या इसकी शुरूआत के समय 66 लाख से बढ़कर 2022 में 1.4 करोड़ हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे व्यवसाय भी इस व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं।पिछले नौ वर्षों में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक विकास एजेंडे के लिए निजी क्षेत्र के साथ सरकार की सहभागिता में परिवर्तन है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति शुरू की गई है, ताकि सरकार की उपस्थिति को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और विशेषज्ञों को घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा विनिर्माण उद्योग में वैश्विक चैंपियन विकसित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान किए जा सकें।एफडीआई नीति को और अधिक उदार बनाया

गया है, अब अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुल गए हैं। 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत छोटे आर्थिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से पिछले वर्षों में व्यापार करने में आसानी में काफी वृद्धि हुई है। सुधार के बाद, 1400 से अधिक डिफ़ॉल्ट मामलों को अदालत का सहारा लिए बिना तय किया गया है। इस दिशा में एंजल टैक्स को शिथिल करना और पूर्वव्यापी प्रतिबद्धता को हटाना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रगतिशील सुधारों से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर 2023 में 98000 से अधिक हो गई है।सरकार ने 2014 से बुनियादी ढांचे और रसद बाधाओं को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्च किया है - सड़क संपर्क (भारतमाला), बंदरगाह बुनियादी ढांचा (सागरमाला), विद्युतीकरण, रेलवे उन्नयन और नए हवाई अड्डे / हवाई मार्ग (उड़ान), अन्य के अलावा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को सक्षम किया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान किए गए सभी सुधार प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग रहे हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे ने डिजिटल पहचान बनाने, वित्त तक पहुंच में सुधार, बाजार तक पहुंच, लेनदेन लागत को कम करने और कर संग्रह में सुधार करने में सक्षम बनाया है और इस दशक में टिकाऊ और त्वरित आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान किया है।इन सभी उपायों के अलावा यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि समावेशी विकास नीतियां भी पिछले दशक में भारतीयों की नीति के मूल में रही हैं।1. 10.11 करोड़ महिलाओं को घर पर मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिया गया है।2. गरीबों के लिए 11.72 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं।3. 51.6 करोड़ जनधन खाते हैं।4. 3.24 लाभार्थी आवासीय पीएमएवाई मकान5.6.27 करोड़ अस्पताल आयुष्मान भारत योजना।

2014-2024 के निष्कर्ष: परिवर्तनकारी विकास का दशक...

1) इन सुधारों के कारण भारत जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में 7.2% की वृद्धि होगी। और अर्थव्यवस्था रोजगार पैदा कर रही है।

2) सरकार ने 80 करोड़ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2028 तक पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।

3) इस प्रभावशाली महामारी के बाद की रिकवरी ने शहरी बेरोजगारी दर को घटकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। मई 2023 से, 18-25 वर्ष की आयु वर्ग में ईपीएफओ के नए ग्राहकों की संख्या लगातार कुल नए ईपीएफ ग्राहकों के 55 प्रतिशत से अधिक रही है।

4) सरकार तेज़ गति से सड़क नेटवर्क, रेलवे और हवाई नेटवर्क का निर्माण कर रही है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहले 67 वर्षों में 74 हवाई अड्डे बनाए। पिछले नौ वर्षों में यह संख्या दोगुनी हो गई।

5) 2014 में विश्वविद्यालयों की संख्या 723 थी और 2023 में यह बढ़कर 1113 हो जाएगी। अब लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

6) आर्थिक सुधारों के माध्यम से, यह संकट के दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद कर रहा है।

7) वैश्विक महामारी के कारण वित्त वर्ष 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई। वास्तविक जीडीपी में 5.8 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, इस अवधि के दौरान संकट के लिए राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य

प्रतिक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से सरकार की चुस्त प्रतिक्रिया ने भारत की आर्थिक सुधार का समर्थन किया। यह, आर्थिक सुधारों के साथ, संकट के लंबे समय तक चलने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद कर रहा है।

8) सरकार ने यूक्रेन में संघर्ष और बाधित आपूर्ति के बावजूद, कच्चे तेल की खरीद को सही कीमत पर प्रबंधित किया है ताकि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में अठारह महीने से अधिक समय तक वृद्धि न हो।

9) सरकार ने वित्त वर्ष 23 में राज्यों को 50 साल का 1 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया और 50 साल के 1.3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की घोषणा की।

<u>भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ :-</u>

पिछले नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा देखा गया सुधार-आधारित विकास चुनौतियों से रहित नहीं है।

1) एक तेजी से एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में, भारत का विकास दृष्टिकोण न केवल उसके घरेलू प्रदर्शन का एक कार्य है, बल्कि वैश्विक विकास के स्पिलओवर प्रभावों का भी प्रतिबिंब है। भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि और अति-वैश्वीकरण की मंदी के परिणामस्वरूप आगे चलकर मित्र-तटस्थता और ऑनशोरिंग होने की संभावना है, जिसका पहले से ही वैश्विक व्यापार और उसके बाद वैश्विक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है।

2) ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास बनाम ऊर्जा संक्रमण के बीच व्यापार-बंद एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके विभिन्न आयाम हैं: भू-राजनीतिक,तकनीकी, राजकोषीय, आर्थिक और सामाजिक, और अलग-अलग देशों द्वारा अपनाई जा रही नीतिगत कार्रवाइयाँ जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं।

3) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का आगमन दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह विशेष रूप से सेवा क्षेत्रों में रोजगार को लेकर सवाल खड़ा करता है। हाल ही में आईएमएफ के एक पेपर में इस बात को उजागर किया गया था, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि वैश्विक रोजगार का 40 प्रतिशत एआई के संपर्क में है, जिसमें पूरकता के लाभ विस्थापन के जोखिमों के बगल में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, पेपर सुझाव देता है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एआई की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए बुनियादी ढांचे और डिजिटल रूप से कुशल श्रम बल में निवेश करना चाहिए।

4) घरेलू स्तर पर, उद्योग के लिए एक प्रतिभाशाली और उचित रूप से कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सभी स्तरों पर स्कूलों में आयु-उपयुक्त सीखने के परिणाम और एक स्वस्थ और फिट आबादी आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताएं हैं। एक स्वस्थ, शिक्षित और कुशल आबादी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यबल को बढ़ चुनौतियों पर नियंत्रण करने के पिछले कार्य निष्पादन का विवरण उपर्युक्त चुनौतियाँ दुर्गम नहीं हैं। ये मुद्दे सरकार की नीतिगत प्राथमिकता का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य भारतीय युवाओं को प्रासंगिक उद्योग कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। दिसंबर 2023 तक, लगभग 1.3 करोड़ उम्मीदवारों ने पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें से लगभग 24 लाख व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है22। इसी तरह, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं।अक्षय ऊर्जा के विनिर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना और कोयले से दूर जाना, 23जिसके परिणामस्वरूप बड़े जलविद्युत सहित

अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, जिनकी संयुक्त स्थापित क्षमता नवंबर 2023 तक 179.57 गीगावाट है। 1.32 अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, भारत ने पिछले दशक में कुछ प्रमुख कमियों को ताकत में बदलने में सफलता पाई है। ऐसी सफलता की संभावना बहुत कम मानी जाती थी। सरकार ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। पिछले नौ वर्षों में, न केवल देश ने वृहद स्तर पर विकास किया है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक भारतीय लाभार्थी और भारत की आर्थिक सफलता का चालक दोनों बने। समावेशी विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग इसका एक उदाहरण है। 'इंटरनेट इन इंडिया' रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में इंटरनेट की पहुंच 2022 में 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई, जो 2014 से तीन गुना से अधिक बढ़ गई है। आधार भारत में सभी क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम रहा है। इसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 1167 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 34 लाख करोड़ से अधिक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, और औसतन हर महीने 200 करोड़ से अधिक आधार-आधारित प्रमाणीकरण हो रहे हैं। भारत ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या 10 जनवरी, 2024 तक 51.5 करोड़ थी, जो मार्च 2015 से 3.5 गुना वृद्धि है। इस प्रगति के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि लगभग 56 प्रतिशत जन धन खाताधारक महिलाएं हैं और इनमें से दो-तिहाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।26 कोविड महामारी के संकट से सफलतापूर्वक निपटने में भारत को सक्षम बनाने में भी प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण थी। CoWin ऐप के साथ, भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को लागू करने में सफल रहा है, जिसमें 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी को 221 करोड़ टीके लगाए गए हैं। जुलाई 2023 तक भारत ने 431 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, जिनमें से 396 जून 2014 के बाद प्रक्षेपित किए गए हैं। 1.33 संक्षेप में, चुनौतियों से निपटने के लिए भारत का 'मिशन मोड' दृष्टिकोण देश को वर्तमान और उभरती चुनौतियों का सामना करने में अच्छी स्थिति में खड़ा किया है।

भविष्य के लिए सुनहरा सपना –

सभी अनुमानों के अनुसार, भारत की वृद्धि दर मजबूत रहने की उम्मीद है, जिसे वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थिरता का समर्थन प्राप्त है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 24 में वृद्धि का आधिकारिक अनुमान 7.3 प्रतिशत है और मुख्य मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य तक कम होने की उम्मीद है। लचीले सेवा निर्यात और कम तेल आयात लागत के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24-27 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत तक कम हो गया है। यह सकारात्मक विकास दृष्टिकोण सकारात्मक है।डिजिटल क्रांति, उद्यमशीलता का समर्थन करने वाला एक सुविधाजनक नियामक वातावरण, समाज के सबसे कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान पर लक्षित उपाय, सहायक भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए विशिष्ट और जटिल विनिर्माण क्षेत्रों का विकास, और अपने निर्यात बास्केट में विविधता लाने और उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर बढ़ने के प्रयास28। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में किए गए सुधारों ने एक लचीले, साझेदारी आधारित शासन पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी है और अर्थव्यवस्था की स्वस्थ रूप से बढ़ने की क्षमता को बहाल किया है। यह मानने के अच्छे कारण हैं कि भारत के आर्थिक और वित्तीय चक्र लंबे और मजबूत हो गए हैं। नतीजतन, भारत आने वाले वर्षों में निरंतर तेज विकास के

लिए तैयार है। उप-राष्ट्रीय सरकारों के स्तर पर, सुधार जो सुव्यवस्थित विनियामक और अनुपालन दायित्वों और संवेदनशील प्रवर्तन के साथ भारत के एमएसएमई की उत्पादक क्षमता को उन्मुक्त करेंगे, उचित मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और ऐसे उपाय जो बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, आर्थिक विकास में और तेजी लाएंगे। 1.35 वर्ष 2023 राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय के बीच भारत की स्थिति के लिए एक मील का पत्थर था। जी20 प्रेसीडेंसी की मेजबानी करके, जिसने सदस्य देशों को प्रमुख वैश्विक चिंता के मुद्दों पर सहमत होने के लिए एक साथ लाया, भू-राजनीतिक मामलों पर उनके चल रहे मतभेदों के बावजूद, भारत ने वैश्विक मंच पर एक प्रमुख आम सहमति निर्माता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत के बढ़ते हिस्से के साथ, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में देश के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल की क्योंकि उसका चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। देश वैश्विक स्तर पर 5G की सबसे तेज़ तैनाती भी हासिल करने में सक्षम रहा। ये उन क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला से सिर्फ़ झलकियाँ हैं जिनमें भारत और उसकी अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में बड़ी प्रगति की है।

स्त्रोत -भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट।

सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक नीति के पहलुओं का एक संक्षिप्त वर्णन जिन्होंने कोविड के बाद की आर्थिक लचीलापन में योगदान दिया है और भारत को आने वाले वर्षों में निरंतर आर्थिक विकास के मार्ग पर स्थापित किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारक है- महामारी के बाद की रिकवरी वित्त वर्ष 2011 में महामारी से प्रेरित संकुचन के बाद लगातार 2 वर्षों में 7% से अधिक की वृद्धि के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया। वित्त वर्ष 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अनुमान के पहले अग्रिम अनुमान से वित्त वर्ष 2024 में अनुमानित वास्तविक जीडीपी विधि 7.3% होने का संकेत है ,जो विभिन्न एजेंसियों के पूर्वानुमान से अधिक है। आरबीआई के 7% के अनुमान से अधिक वृद्धि की संभावना है। जो मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का भी संकेत देकर सकारात्मक आकलन देती है।

एकाधिक आयामो में लचीलापन आर्थिक वृद्धि: बेरोजगारी दर में गिरावट एवं बढ़ती आर्थिक गतिविधि में लचीलापन स्पष्ट है। ई- वे बिल जेनरेशन, रेल मार्ग ,ढुलाई एवं बंदरगाह ,कार्गो यातायात सहित उच्च आवृत्ति संकेतको में स्पष्ट प्रदर्शन दर्शाते हैं। बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने तथा आवास के बढ़ती मांग के कारण निर्माण गतिविधि में वृद्धि हुई है ,जो स्टील की खपत के साथ -साथ सीमेंट उत्पादन की वृद्धि में परिलक्षित होती है। महामारी की चुनौतियों के बावजूद गतिशीलता विशेष रूप से हवाई यात्रा, पूर्व कोविड स्तर से अधिक हो गई। बैंकिंग क्षेत्र एवं राजकोषीय अनुशासन: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट आरबीआई की परिसम्पतियों की गुणवत्ता समीक्षा, पूर्व पंजीकरण तथा दिवालिया और शोधनता अक्षमता को आईबीसी के अधिनियम में निहित हो। महामारी से पूर्व विकास प्रेरकों की निरंतरता ऊर्जा सुरक्षा एवं घरेलू मांग पर निर्मित लचीलापन भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च विकास को बनाए रखते हैं ।10 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए चार खंडों के पहचाने गए उपाय घरेलू अर्थव्यवस्था, व्यापार आर्थिक की सुविधा मानव संसाधन एवं बाह्य अर्थव्यवस्था। जलवायु परिवर्तन के

प्रतिरोध को मजबूत कर ऊर्जा सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन की खोज को प्रोत्साहित करना।

घरेलू अर्थव्यवस्था कोविड के बाद वित्त वर्ष 2022 तथा वित्त वर्ष 2024 के बीच औसतन 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है ।

मेक इन इंडिया मिशन के कारण सरकार मूल्य वर्धित जीवीए (GVA) में विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी 17.2% वित्त वर्ष 2014 से बढ़कर 18.4% वित्त वर्ष 2018 हो गई है।

कुल GVA में निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 8.8% वित्त वर्ष 2014 थी और साथ ही रियल एस्टेट मूल्य वृद्धि तथा महामारी चुनौतियों का मुकाबला करने के बाद लगभग 8.7% वित्त वर्ष 2024 तक पहुंच गई।

कुल GVA में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 51.1% से वित्त वर्ष 2014 से बढ़कर 54.6% 2024 हो गए। इसे गैर संपर्क सेवा में वृद्धि हुई । डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार का अभियान जिसका प्रतिनिधित्व इंडिया स्टैक द्वारा किया जाता है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आंकड़ों का विश्लेषण द्वारा प्रदर्शित हैं -

1. निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE)

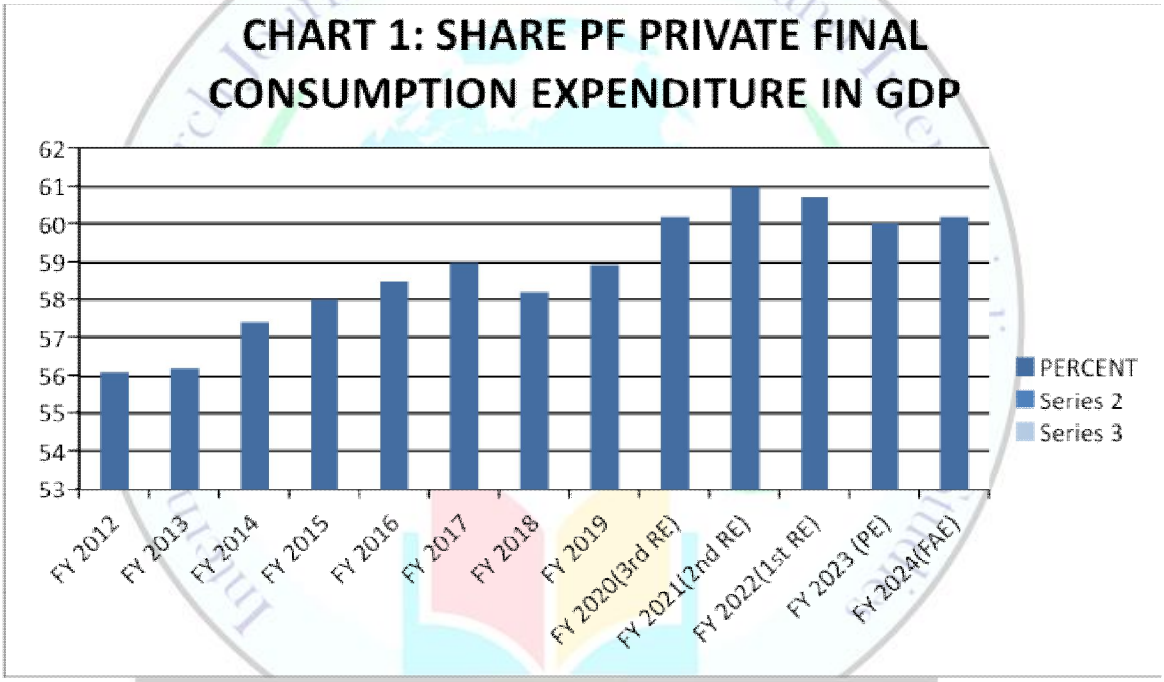

SOURCES: NSO, MOSPI

NOTE: RE STANDS FOR REVISED ESTIMATES, PE FOR PROVISIONAL ESTIMATES AND FAE FOR FIRST ADVANCE ESTIMATES.

मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में पीएफसीएफ की हिस्सेदारी महामारी से पहले के 8 वर्षों में औसतन 58.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में 60.8% हो गई।

2. **महामारी से पहले के 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति वास्तविक सरकार राष्ट्रीय आय** (GNI) में मजबूत वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2020 तक 5.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर (CAGR) दर्ज की ।सुदृढ सरकारी जिला कौन बाजार अनुकूलन सुधार अनुपालन भोज काम करना सैलरी कट कानून क्षेत्र को खोलने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को रणनीतिक विनिवेश ने निजी क्षेत्र के विकास में योगदान दिया।

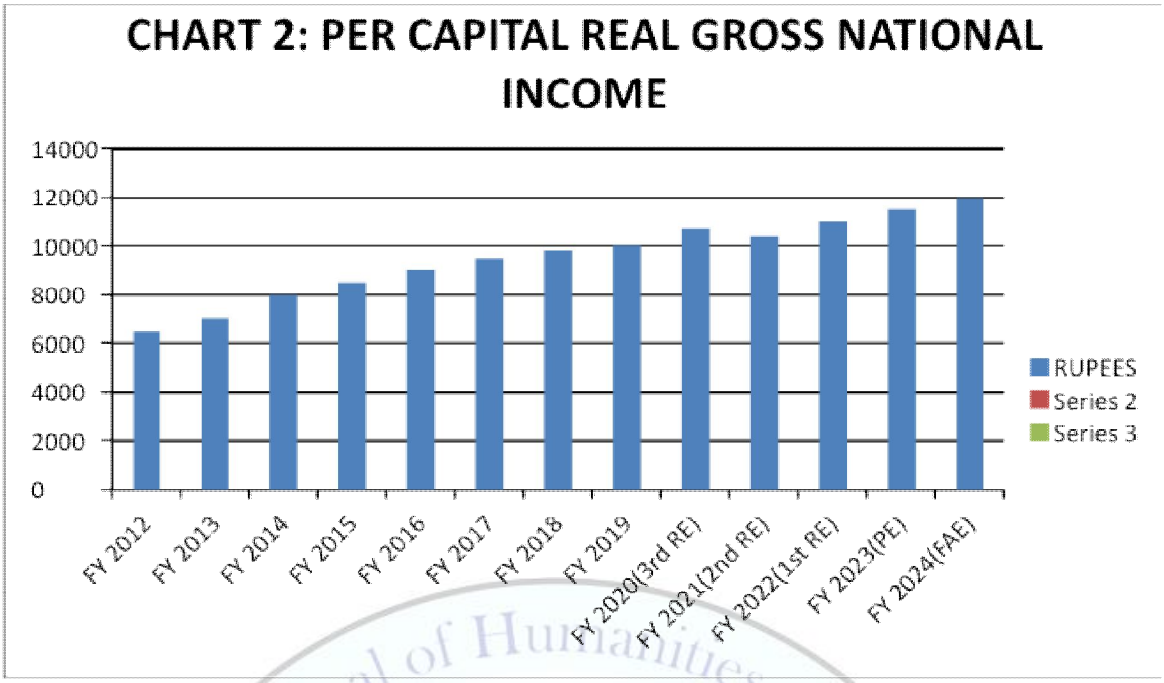

SOURCES: NSO,MOSPI

NOTE: RE STANDS FOR REVISED ESTIMATES, PE FOR PROVISIONAL ESTIMATES AND FAE FOR FIRST ADVANCE ESTIMATES.

3. **निवेश हेतु आउटलुक** निवेश और ऋण में वृद्धि के परिणामस्वरुप पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक रूझान प्रदर्शित किए हैं ।प्रस्तुत ग्राफ में आंकड़े इस दावे का समर्थन करते हैं कि मौजूदा दशक में निवेश तथा ऋण बढ़ने की संभावना है। प्रयासों के परिणामस्वरूप निजी कॉपरेटिव एवं बैंकिंग क्षेत्र दोनों में स्वरुप बैलेंस सीट प्राप्त हुई है।

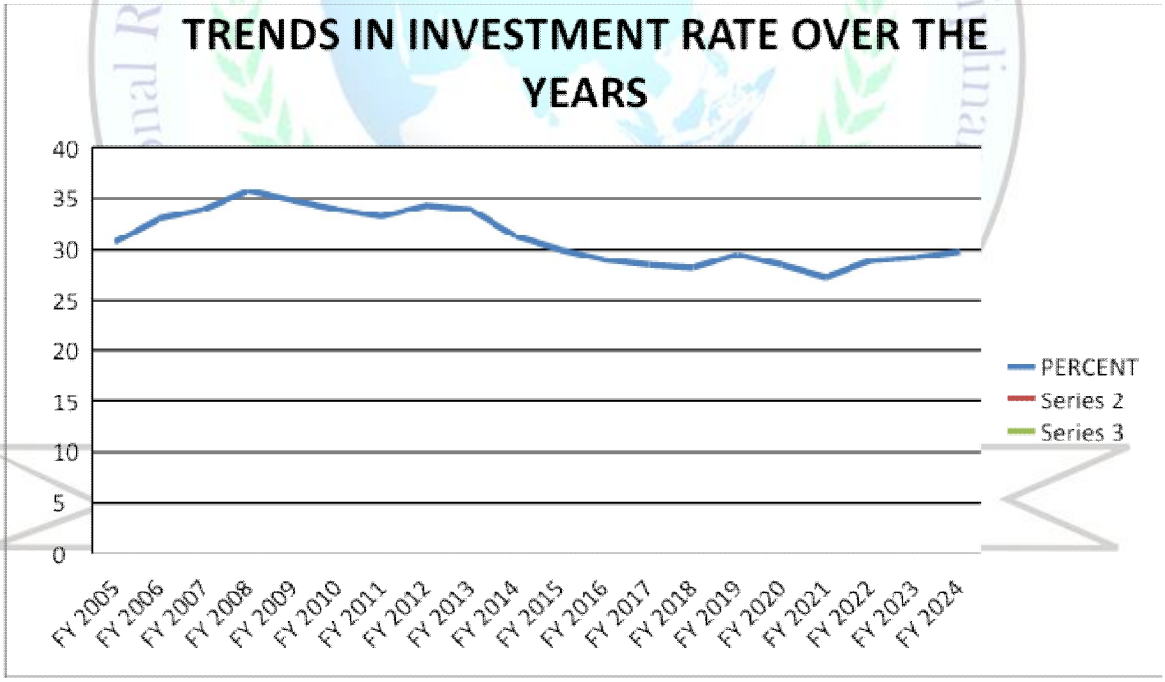

SOURCES NSO, MoSPI

NOTE INVESTMENT RATE IS THE RATIO OF NOMINAL GFCF OVER NOMINAL GDP.

FY 2005FY 2012 IS UNSUTAINABLE CREDIT BOOM SND BAD DEBT MOUNTING.

FY 2013 TO FY 2020 IS BALANCES SHEET REPAIR (CORPORATE AND BANKS), RISK AVERSION LEADING TO RELCTANCES IN LENDING.

FY 2021 TO FY 2024 IS PHASE OF GROETH AND INVESTMENT RECOVERY.

4. **गैर -खाद्य बैंक ऋण वृद्धि:-** व्यक्तिगत ऋणों को छोड़कर वर्ष 2008 में 20% से घटकर वित्त वर्ष 2016 में 10% से भी काम हो गई थी ।वित्त वर्ष 2023 में 13% के साथ वृद्धि हुई है।

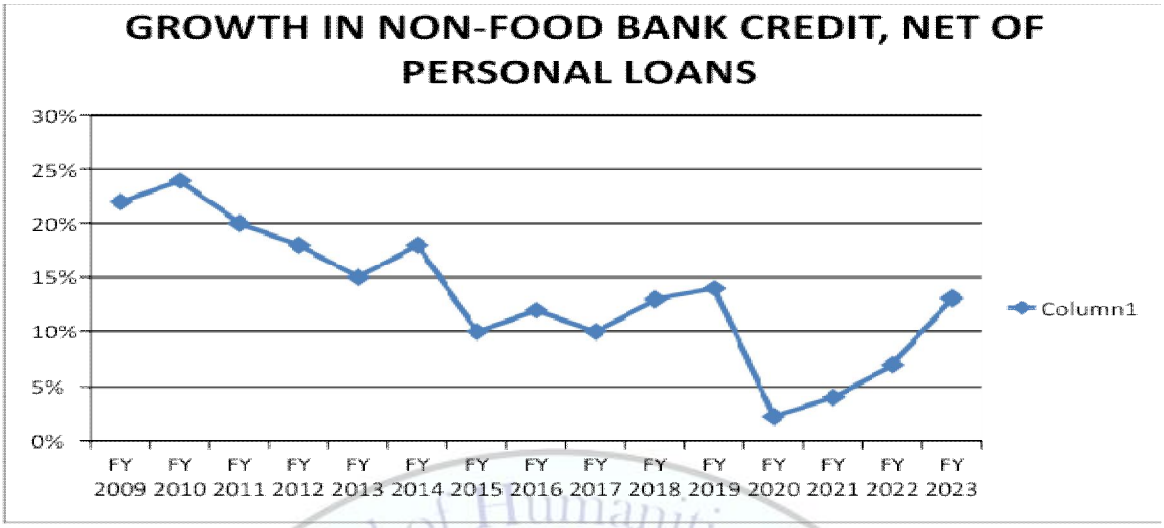

SOURCES RBI

NOTE: FY 2009 TO FY 2012 UNSUTAINABLE CREDIT BOOM AND BAD DEBT MOUNTING.

FY 2013 TOFY 2020 IS BALANCES SHEET REPAIR (CORPORATE AND BANK), RISKS AVERSION LENDING TO RELUCTANCE IN LENDING.

FY 2020 TO FY 2023 IS LENDING RESUMES.

5. **सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत वर्ष 2015 से 2024 केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय:-** पूंजीगत संपत्ति निर्माण हेतु राज्यों को अनुदान एवं केंद्रीय पीएसई के निवेश संसाधनों सहित सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2015 में 5.6 रुपए लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में रुपए 18.6 लाख करोड़ हो गया ।इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 5.1 गुना की वृद्धि हुई ।राज्यों के अनुदान में 2.8 गुना की वृद्धि ,साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संसाधनों में 2.1 गुना के वृद्धि हुई ।राजकोषीय व्यय का पुनर्संतुलन वित्त वर्ष 2018 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 12% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 22% (बजट अनुमान) हो गया।

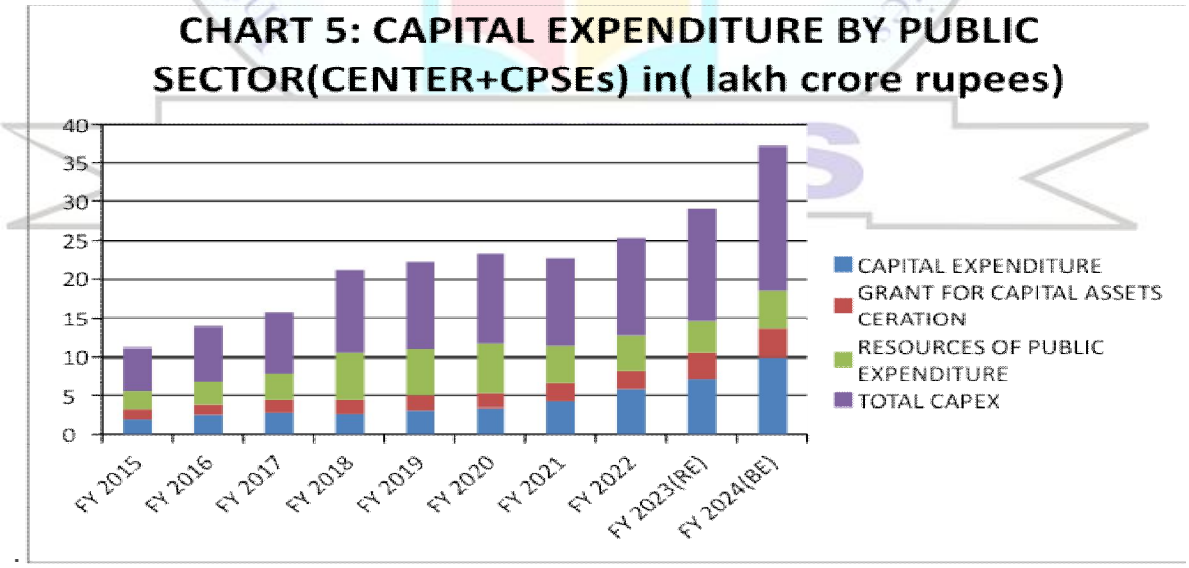

DATA SOURCES- VARIOUS BUDGET DOCUMENTS

6. **बुनियादी ढांचे पर निवेश पर जोर-** बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर देखकर भारतीय अर्थव्यवस्था में चली आ रही आपूर्ति पक्ष की कमियों को दूर करना है।

बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने हेतु सरकारी उपाय:

सरकार ने निर्माण में देरी, प्रशासनिक अक्षमताओं, वित्तपोषण चुनौतियों, कानूनी जटिलताओं के साथ-साथ भूमि मुद्दों जैसे मुद्दों को संबोधित करके रुकी हुई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की एक बड़ी पाइपलाइन पर काम तेज़ कर दिया है।सरकार द्वारा नौकरशाही प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत किया, परियोजना अनुमोदन को सुव्यवस्थित किया, कानूनी बाधाओं को कम किया, कॉर्पोरेट कर दरों को कम किया, एक समान GST व्यवस्था लागू की और निजी निवेशकों के लिये नए रास्ते खोले।प्रगति एवं परियोजना निगरानी समूह (PMG) तंत्र ने लंबे समय से विलंबित परियोजनाओं के निष्पादन में तेज़ी लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।कई प्रॉक्सी संकेतक एवं उद्योग रिपोर्ट महामारी के बाद के वर्षों में निजी पूंजीगत व्यय चक्र के नए उद्भव का सुझाव देते हैं।औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) डेटा वित्त वर्ष 2013 में पूंजीगत सामान सूचकांक (12.9%) और बुनियादी ढाँचे एवं निर्माण सामान सूचकांक (8.4%) में मज़बूत वृद्धि का संकेत देता है। सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध कॉरपोरेट वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में निजी निवेश बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं।

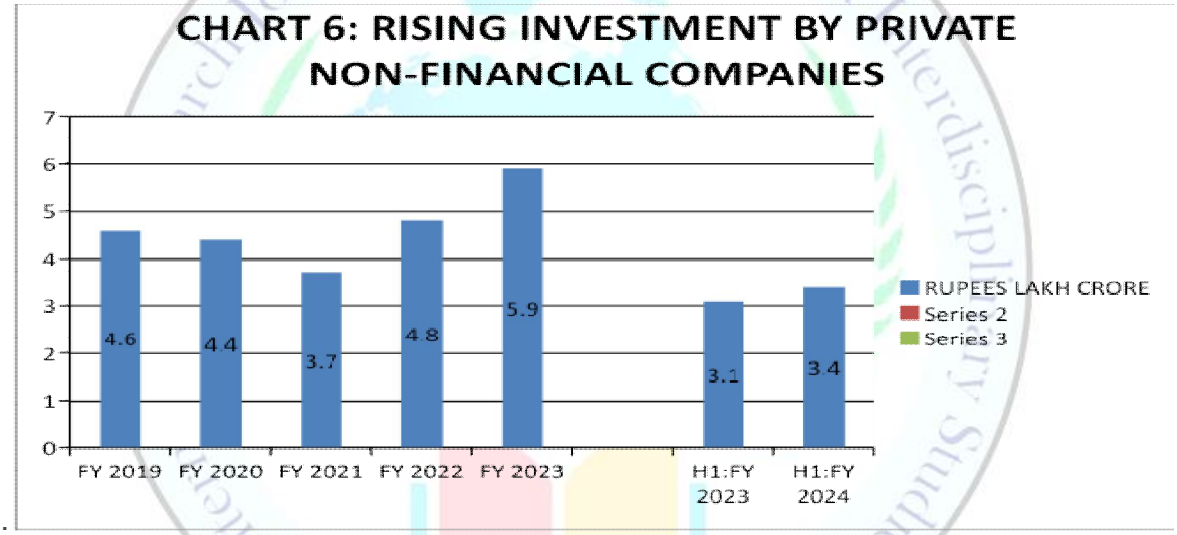

SOURCES: AXIS BANK RESEARCH
NOTE: DATA IS FOR A SET OF 3,336 COMPANIES.

7. **रियल एस्टेट में घरेलू निवेश बढ़ने से निवेश दर मज़बूत होती है**: घरेलू क्षेत्र का निवेश योगदान कुल सकल स्थिर पूंजी निर्माण में घरेलू क्षेत्र निवेश का हिस्सा सबसे बड़ा है । महामारी से ठीक पहले घरेलू क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हो रही थी । अचल संपत्ति की कीमतों में वृद्धि में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई और साथ ही आवास हेतु बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप घरेलू क्षेत्र के निवेश भी में वृद्धि हुई।महामारी के बाद, आवास की कीमतों में सुधार के साथ औसत वार्षिक वृद्धि वित्त वर्ष 2012 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 की पहली छमाही में 4.3% हो गई है।यहाँ तक कि बढ़ती ब्याज दरों तथा रियल एस्टेट की कीमतों के बावजूद, आवासीय बिक्री में बढ़ोतरी आय वसूली के लचीलेपन के साथ भविष्य के लिये आशावाद को दर्शाती है ।

निवेश दर में सतत् वृद्धि:

पिछले तीन वर्षों से अर्थव्यवस्था की समग्र निवेश दर लगातार सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वित्त वर्ष

2016 के स्तर को पार कर गई है।निवेश में वृद्धि अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्रों- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं घरेलू द्वारा संचालित है।यह देश की भविष्य की आर्थिक संभावनाओं के प्रति विश्वास को दर्शाता है।निवेश दर में निरंतर वृद्धि से अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश आधारित विकास की नींव रखने की आशा है ।

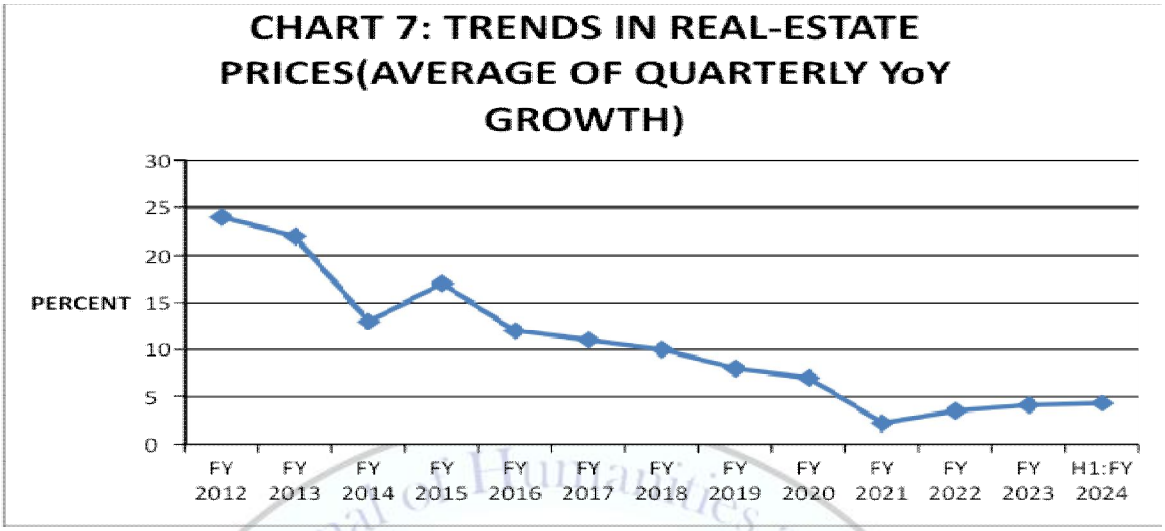

POST-PANDEMIC PICK-UP IN GROETH IN REAL-ESTATE PRICES. FY2021-FY 2024(2.2-4.3)

SOURCES RBI

NOTE: THE FIGURE FOR H1FY2024 IS AN AVERAGE OF QUARTERLY YoY GROWTH FOR THE FIRST TWO QUARTERS OF 2024.

8.बुनियादी ढाँचा:राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) 8 मंत्रालयों की 35 प्रणालियों के साथ एकीकृत है, जिसमें 699 उद्योग भागीदार पंजीकृत हैं।वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2022 के बीच अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 से 0.9 प्रतिशत अंक तक कम हो गई।प्रमुख बंदरगाहों पर औसत टर्नअराउंड टाइम 4.2 दिन (FY04-FY14) से घटकर 2.9 दिन (FY14-FY22) हो गया।सरकार के पूंजीगत व्यय ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर दिया, निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया, और FY22 से FY24 तक निर्माण में लगभग 12% प्रति वर्ष की वृद्धि में योगदान दिया।.

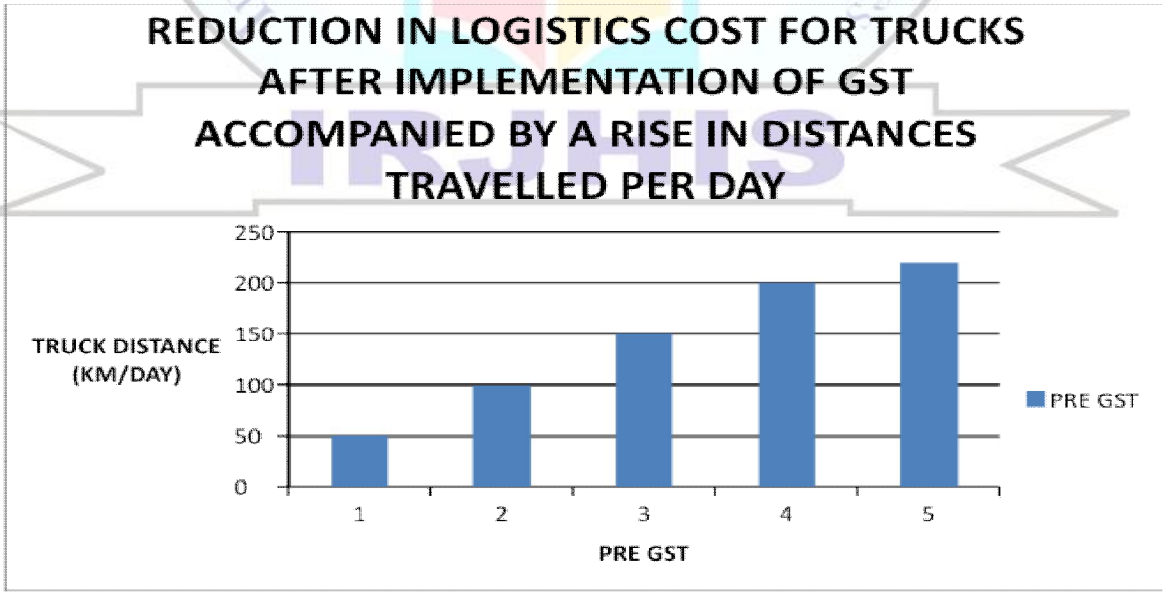

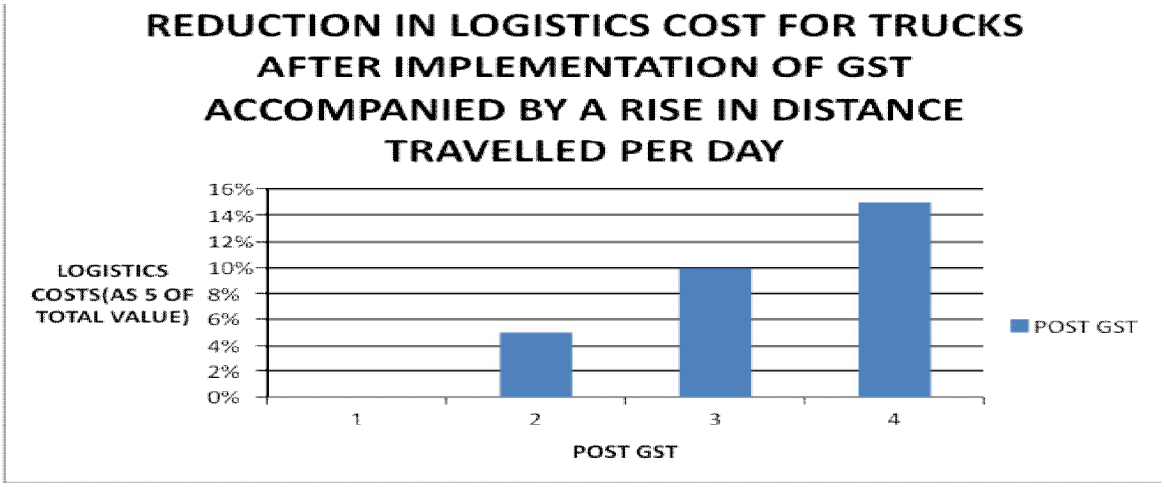

SOURCES: MINISTARY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS.

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) - इंडिया स्टैक:तीन परस्पर संबद्ध स्तर: पहचान स्तर (आधार), भुगतान स्तर (UPI, आधार भुगतान ब्रिज, आधार सक्षम भुगतान सेवा) और डेटा स्तर (अकाउंट एग्रीगेटर)।आइडेंटिटी लेयर/पहचान स्तर (आधार) ने हर भारतीय को डिजिटल पहचान प्रदान की।पेमेंट लेयर/भुगतान स्तर में कैशलेस भुगतान में वृद्धि देखी गई, विशेषकर महामारी के दौरान।डेटा लेयर ने प्रामाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया, e-KYC लागत को ₹1000 से घटाकर ₹5 कर दिया।PMJDY और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):PMJDY ने लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfers- DBT) के लिये इंडिया स्टैक का प्रयोग किया।

PMJDY खाते मार्च 2015 में 14.7 करोड़ से तीन गुना बढ़कर 10 जनवरी 2024 तक 51.5 करोड़ हो गए।DBT मोड में दिसंबर 2023 तक ₹33.6 लाख करोड़ से अधिक का हस्तांतरण हुआ।

वित्तीय समावेशन और फिनटेक विकास : टेलीकॉम क्षेत्र में 100% FDI और भेदभावपूर्ण डेटा टैरिफ पर रोक से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी।प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत मासिक डेटा खपत मार्च 2014 में 61.7 MB से लगभग 300 गुना बढ़कर जून 2023 में 18.4 GB हो गई।भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ते फिनटेक बाज़ारों में से एक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC): भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के प्रसार से जुड़ी व्यावसायिक सेवा के निर्यात में तीव्र वृद्धि। GCC का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1% से अधिक का योगदान है।

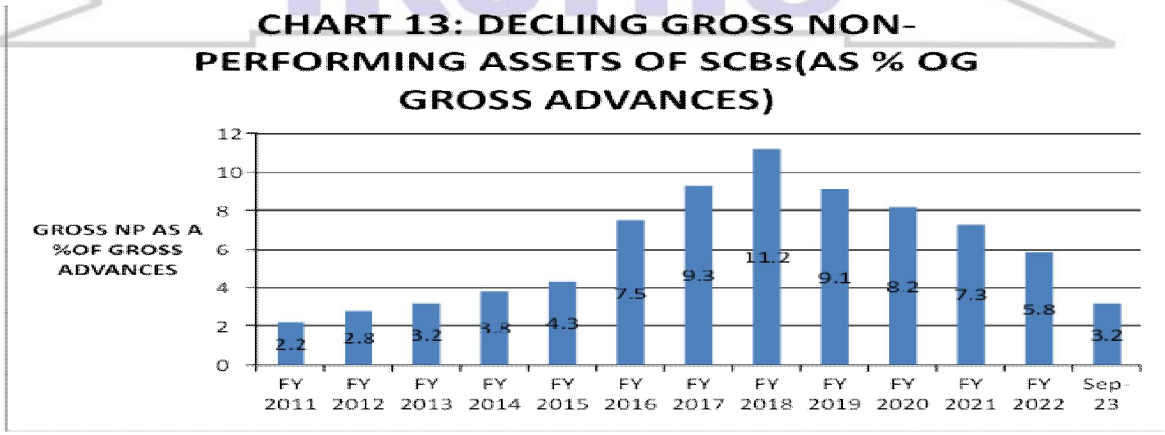

SOURCES RBI

क्रेडिट सृजन की वापसी :- बैंक ऋण वृद्धि:जमाराशियों में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया।वित्त वर्ष 2013 में गैर-खाद्य बैंक ऋण 15% की दर से बढ़ा, जो पिछले दशक में सबसे अधिक है।परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार:सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) समूहों में संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार।कुल अग्रिमों के सापेक्ष GNPA और शुद्ध NPA के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति। यह संपत्ति की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी का प्रतीक है।

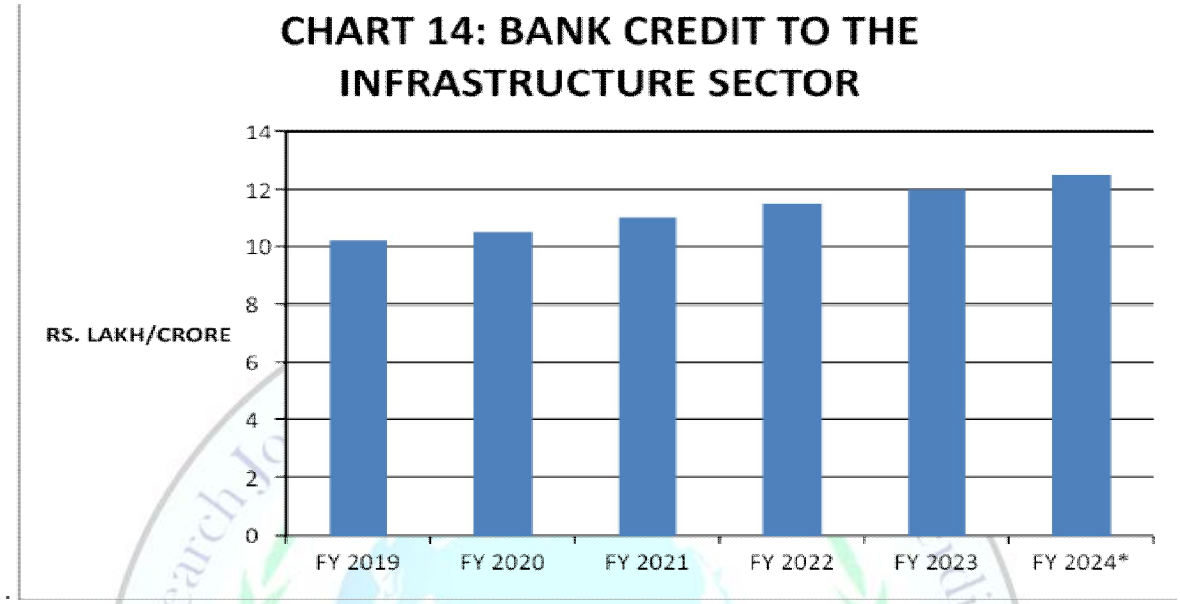

SOURCES-RBI
NOTE-*DATA FOR FY 2024 IS AS OF 17th NOV 2023.

वृहद आर्थिक स्थिरता की संरक्षा :-

वृहद आर्थिक स्थिरता/स्थायित्व लक्ष्य:उत्पादन में निरंतर वृद्धि, मूल्य स्थिरता और एक सुदृढ़ बाह्य/विदेशी खाता के माध्यम से सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक का लक्ष्य वृहद आर्थिक स्थिरता है।विभिन्न चुनौतियों के बावजूद संस्थागत रूपरेखा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।मुद्रास्फीति:FY09 और FY14 के बीच की अवधि में उच्च औसत खुदरा मुद्रास्फीति देखी गई लेकिन FY16 के बाद से मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते (Monetary Policy Framework Agreement) के तहत 4 +/- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाया गया है।मूल्य/कीमत स्थिरीकरण कोष (Price Stabilization Fund- PSF) कृषि-बागवानी वस्तुओं में मूल्य अस्थिरता के प्रबंधन में प्रभावी रहा है।कोविड-19 महामारी के दौरान मौजूद चुनौतियों के बावजूद, PSF और बेहतर राजकोषीय तथा बाह्य संतुलन की मदद से मुद्रास्फीति को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखा गया।महामारी के बाद की चुनौतियाँ और प्रतिक्रिया:FY22 में आर्थिक सुधार देखा गया किंतु FY22 के अंत तक भू-राजनीतिक संघर्षों और प्रतिबंधों के कारण वैश्विक आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई।वैश्विक स्तर पर जिंस/पण्य (Commodity), विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा। सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिये ऊर्जा आपूर्ति स्रोतों में विस्तार किया जिससे भारत के विकास पुनरुद्धार में योगदान मिला।

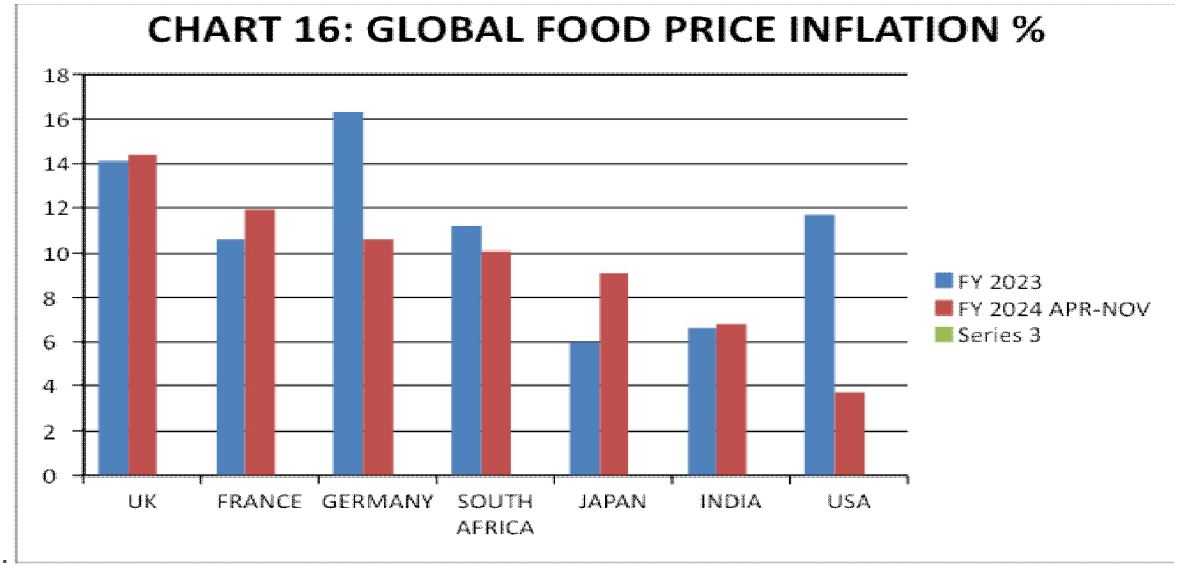

NOTE- MoSPI FOR INDIA AND OECD FOR OTHER COUNTRIES.

मुद्रास्फीति के रुझान : वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति का स्तर कम हुआ और औसत खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.5 प्रतिशत हुई।दिसंबर 2023 में कोर मुद्रास्फीति 49 माह के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर पहुँच गई।समग्र खुदरा मुद्रास्फीति स्थिर है और 2 से 6 प्रतिशत के अधिसूचित सहन (Tolerance) बैंड के भीतर है।

स्त्रोत -दृष्टि द विज़न

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष के तौर पर, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में तमाम जोखिमों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत लचीलापन और प्रगति दोनों दिखा रहा है। मैक्रो स्थिरता हासिल करने और वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों की बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के उद्देश्य से समय पर और प्रभावी नीतिगत कार्रवाइयों के साथ-साथ विश्व स्तरीय भौतिक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश करके भारत घरेलू और वैश्विक दोनों चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है और यह सुनिश्चित किया है कि अर्थव्यवस्था स्थिर पथ पर आगे बढ़ती रहे। सरकार द्वारा पहले ही लागू किए गए और जिन नीतिगत सुधारों पर काम चल रहा है, उनके साथ आज भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी संभावनाओं में काफी आशावाद और विश्वास है। भारत अपने 'अमृत काल' पर आत्मविश्वास और इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है कि विकास और समावेशी विकास की चुनौतियाँ बाधाएँ नहीं बल्कि कदम हैं। 1.37 पिछले दस वर्षों में भारत ने जो रास्ता तय किया है, वह न केवल सरकार के विजन को दर्शाता है, बल्कि उसके नागरिकों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है, जो विश्वास के आधार पर स्थापित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सही ढंग से समझा है। भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज, यह 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (अनुमानित 2024) के सकल घरेलू उत्पाद के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस दस वर्ष की यात्रा में अनेक सुधार हुए हैं, जो सारवान और वृद्धिशील दोनों हैं, जिन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान बाजार मूल्य पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगले वर्ष भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है, 2047 तक सुधारों की यात्रा जारी रहने के साथ एक "विकसित देश" बन जाएगा, यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस लक्ष्य की ताकत घरेलू

मांग की मजबूती से 7% जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में आपूर्ति निवेश से विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, निवेश का माहौल बढ़ रहा है और कारोबार में सतत वृद्धि के साथ यह अधिक अनुकूल होता जा रहा है। जीएसटी सुविधाएं संघ और राज्य सरकार के वित्त को मजबूत करेंगी, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी।आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच पांच साल की अवधि में विकास दर समान थी। इसलिए, वित्तीय क्षेत्र की ताकत पर आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% से अधिक की दर से बढ़ना संभव है। आगे के सुधारों के लिए सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्कीइंग, सीखने के परिणाम, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, एमएसएमई के लिए तुलना ब्यूरो में कमी और श्रम बल में लिंग संतुलन शामिल हैं। भारत 2030 में 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा कर सकता है। राज्य सरकार, जिला, ब्लॉक, गांव, नागरिकों और छोटे व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि और ऋण की पूर्ण भागीदारी के साथ सुधार अधिक उद्देश्यपूर्ण और फलदायी होंगे, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक प्रभावशाली और बड़ी भूमिका होगी।

संदर्भ -

1. बी.बी.भट्टाचार्य और सब्यसाचिकर झटके, आर्थिक विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था"

2. अरविंद विरमानी (2005) "भारत का आर्थिक विकास इतिहास: उतार-चढ़ाव, रुझान, ब्रेक प्वाइंट और चरण।"

3. धार, पी.एन. (1988), भारतीय अर्थव्यवस्था: विगत प्रदर्शन और वर्तमान मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था में: हाल के विकास और भविष्य की संभावनाएं, रॉबर्ट ई.बी. लुकास और गुस्लाव एफ. पापंकर द्वारा संपादित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आई.एस.आर.एस.एल.

4. राघवेंद्र झा,(2007)"भारतीय अर्थव्यवस्था: वर्तमान प्रदर्शन और अल्पकालिक संभावनाएं."एसएसआरएन जर्नल

5. आर्थिक विभाग (भारत सरकार)

6. नम्रता आनंद, (2014) "भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन (1991-2013)" आर्थिक और वित्त का जर्नल।

7. एम.के. अग्रवाल, 2024 "भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिमान बदलाव"

8. दृष्टि द विजन।